भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
13.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2180 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2180. श्री नीरज डांगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के अंतर्गत सरकार का कितने स्टेशनों को उन्नत और आधुनिक बनाने का लक्ष्य है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कवर किए गए स्टेशनों का मंडल-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास के लिए सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास के लिए, विशेष रूप से राजस्थान राज्य में, कितने स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म पर शेल्टर लगाना, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन

एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाऊंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 85 स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान राज्य में चिन्हित किए गए स्टेशनों की सूची निम्नानुसार है:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशन
राजस्थान	85	आबूरोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, असलपुर जोबनेर, बालोतरा, बांदीकुई, बारन, बाड़मेर, बयाना, ब्यावर, भरतपुर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, बिजयनगर, बीकानेर, बूंदी, चंदेरिया, छबड़ा गुगोर, चित्तौड़गढ़ जं., चूरू, डकनिया तलाव, दौसा, डीग, डेगाना, देशनोक, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जवाई बांध, झालावाड़ सिटी, झुंझुनू, जोधपुर, कपासन, खैरथल, खेरली, कोटा, लालगढ़, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मारवाड़ भीनमाल, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, मेड़ता रोड, नागौर, नरैना, नीम का थाना, नोखा, पाली मारवाड़, फलौदी, फुलेरा, पिंडवाड़ा, रायसिंह नगर, राजगढ़, रामदेवरा, रामगंज मंडी, राणा प्रतापनगर, रानी, रतनगढ़, रेन, रींगस, सादुलपुर, सांगानेर, सवाई माधोपुर, श्री महावीरजी, सीकर, सोजत रोड, सोमेसर, श्री गंगानगर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर सिटी,

राजस्थान राज्य में स्थित 85 अमृत स्टेशनों में से 79 स्टेशनों के लिए विकास कार्यों की

निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और कार्य शुरू हो चुका है। परियोजनाओं के निष्पादन की गति अच्छी है। उदाहरण के लिए,

- गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर, दोनों तरफ के स्टेशन भवनों के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, एयर कॉनकोर्स के गर्डर और डेक स्लैब लगा दिए गए हैं और थ्रू रूफ और प्लेटफॉर्म शेल्टर आदि का निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है।
- जयपुर जंक्शन स्टेशन पर, बेसमेंट सहित द्वितीय प्रवेश भवन के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं और पैदल पार पुल, मुख्य साइड स्टेशन भवन, एयर कॉनकोर्स आदि का कार्य शुरू किया जा चुका है।
- जैसलमेर स्टेशन पर, मुख्य स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, एयर कॉनकोर्स और फुट ओवर ब्रिज के गर्डर और डेक स्लैब लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है।
- उदयपुर सिटी स्टेशन पर, स्टेशन भवन के पूर्वी ओर संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं और पश्चिम की ओर के स्टेशन भवन, एयर कॉनकोर्स, थ्रू रूफ, फुट ओवर ब्रिज, स्काईवॉक आदि का कार्य शुरू किया जा चुका है।
- कोटा जंक्शन स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान हॉल और विद्युत सबस्टेशन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है तथा स्टेशन भवन के पीछे की ओर मुख्य प्रवेश द्वार की ओर आगमन हॉल, एयर कॉनकोर्स, थ्रू रूफ आदि का कार्य शुरू हो गया है।
- डकनिया तलाव स्टेशन पर दोनों ओर स्टेशन भवन, पार्सल कार्यालय, विद्युत सबस्टेशन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है तथा एयर कॉनकोर्स, थ्रू रूफ, नए यात्री प्लेटफार्म आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

SK

भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्य को स्वीकृति देने और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के उन्नयन/विकास/आधुनिकीकरण को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 “यात्री सुविधाएं” के तहत आबंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत भारतीय रेल हेतु कुल आबंटन 15,511 करोड़ रुपये है। राजस्थान राज्य पांच क्षेत्रीय रेलवे अर्थात उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए आबंटन 6952 करोड़ रुपये है।

*****

SK